



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, १९ सितम्बर, १९९२/२८ भाद्रपद, १९१४

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएँ

शिमला-२, १० सितम्बर, १९९२

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (४) ३०/७६-८. —राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९६८ (१९७० का संख्यांक १९) की धाराओं ४ (१) तथा ५ (१) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिजा ऊना के विकास खण्ड बंगाणा की ग्राम सभा “हटली (जसाना)” का नाम बदल कर “जसाना” रखने का सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-२, १४ सितम्बर, १९९२

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (१) ८५/९०. —इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक १ जुलाई, १९९२ का प्रसंग जारी रखते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पंचायती राज विभाग में उच्च शक्तिय समिति की अवधि २५-८-१९९२ तक बढ़ाने का सहर्ष कार्यांतर आदेश देते हैं। समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सम्बन्धी शर्तों आदि पर किसी प्रकार का परिवर्तन न होगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 14 सितम्बर, 1992

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 65/91.-—क्योंकि ग्राम पंचायत नैना टिक्कर, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर का अंकेक्षण करवाने के फलस्वरूप श्री नित्या नन्द तत्कालीन प्रधान, ग्राम पंचायत नैना टिक्कर के विरुद्ध अनुदान की राशि का गबन, पंचायत निधि का छलहरण तथा प्रधान पद के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया ;

क्योंकि उपरोक्त कृत्य के लिए श्री नित्यानन्द तत्कालीन प्रधान को प्रधान पद से निलम्बित किया गया और इस मामले की वास्तविकता जानने के लिए आदेश संख्या पी० सी० एच०-एच०-ए० (5) 65/91, दिनांक 20-12-91 के अन्तर्गत उपनण्डलाधिकारी (ना०) राजगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था;

और क्योंकि हाल ही में हुए पंचायतों के चुनाव में श्री नित्यानन्द, पंचायत के किसी पद पर निर्वाचित न हो सके तथा उनके विरुद्ध उपरोक्त जांच में लगाए गये आरोपों से सम्बद्ध फौजदारी व दिवानी मुकद्दमें दायर करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त मामले में जांच जारी रखने का औचित्य नहीं रहा और श्री नित्यानन्द भूःपूर्व प्रधान के जिम्मा जो राशि वसूली योग्य है की वसूली की कार्यवाही शीघ्र करने के उद्देश्य से जांच वापिस ली जाये।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के प्रयोग में जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 (4) के अन्तर्गत प्राप्त हैं उपरोक्त मामले में चल रही जांच को तुरन्त बन्द करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव (पंचायत)।